

प्रेषक,

आर०के० सुधाशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग
निदेशालय, 107 चन्दर नगर
देहरादून।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

विषय:-

देहरादून: दिनांक 23 जनवरी, 2015।

राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी में Multi Disciplinary Research Unit स्थापना हेतु सिविल रिनोवेसन एवं मिनी कोल्ड लैब के कार्यों हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 26प/चि०कि०/82/2012/2997 दिनांक 20.10.2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप द्वारा प्रदत्त संस्तुतिनुसार राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी में Multi Disciplinary Research Unit स्थापना हेतु सिविल रिनोवेसन एवं मिनी कोल्ड लैब के कार्यों हेतु भारत सरकार से प्राप्त, प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी के निर्वतन पर रखी धनराशि रु० 35.00 लाख को टी०ए०सी० वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 10.75 लाख एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रु० 21.96 लाख अर्थात् कुल ₹ 32.71 (रु० बत्तीस लाख इक्वत्तर हजार मात्र) लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में संगत मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- कार्य पर मदवार उतना की व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताये तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्ट्यों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- निर्माण सापग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्ट्यों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
- विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 15.12.2008 के प्राविधानुसार एम०ओ०यू० हस्तान्तरित किया जायेगा तथा समयसारणी निर्धारित करते हुए कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाना एवं विभाग को हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

- स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
 - मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
 - उक्त व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली -2008 में उल्लिखित प्राविधानों एवं कय के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/नियमों के अधीन सुनिश्चित किया जाय।
 - व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली -2008 के नियम-14 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन न हों।
 - भारत सरकार के अर्द्ध शा. पत्र संख्या- V.25011/72/2014-HR दिनांक 30 जुलाई, 2014 द्वारा निर्गत Guidelines से दिये गये दिशा - निर्देशों एवं भारत सरकार से समय-समय पर निर्गत आदेशों का का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
 - उक्त कार्य हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।
- 2- यह आदेश वित्त अनुभाग-3 उत्तराखण्ड शासन के अशा0 सं0-293(P)/XXVII(3)/2014-15, दिनांक 13 जनवरी, 2015 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0 सुधांशु)

सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन को मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी नैनीताल।
7. महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम नेहरू कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून।
8. परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, इकाई हल्द्वानी।
9. एन0 आई0 सी0 /गोर्ड फाईल।

आज्ञा से,

माया

(मायावती ढकरियाल)

संयुक्त सचिव।